ट्रैफिक व्यवस्था पर किया मंथन

भोपाल, 03 सितंबर .सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में भोपाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई.

बैठक में शहर के लेफ्ट टर्न और ब्लैक स्पॉट्स संबंधी पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई. सांसद शर्मा ने निर्देश दिए कि ट्रैफिक रूट में आ रहे एमपीईबी के खंभों को शीघ्र हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए.

> कंडम वाहनों की कार्यवाही को गति प्रदान करने पर बल दिया. उन्होंने भोपाल शहर में सर्वेलेंस कैमरे लगाए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए. बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा तिवारी, एडिशनल डीसीपी बसंत कोल, एसीपी ट्रैफिक अजय बाजपेयी, विजय दुबे, सभी एसडीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

राहुल शर्मा बने दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष

भोपाल. राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांताध्यक्ष शीलप्रताप सिंह पुंढीर ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की लंबित एवं ज्वंलत समास्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनका गंभीरता पूर्वक निराकरण कराने के लिए दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ का गठन किया. इसका राहुल शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है. शर्मा वर्तमान में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. शर्मा के मनोनयन पर संगठन महामंत्री व्यासमुनी चैबे आदि बधाई देते प्रांताध्यक्ष शीलप्रताप सिंह पुंढीर का आभार जताया है.

कपास का शुल्क हुआ कम, किसान परेशान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 सितंबर. केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका सहित अन्य देशों से आयातित कपास पर दिसंबर 2025 तक आयात शुल्क समाप्त करने के फैसले ने कपास उत्पादक किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है.

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अक्टूबर से देशभर में किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं. किसान नेताओं का कहना है कि इस कदम से देशी कपास की मांग घटेगी और किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाएगा. पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सस्ता विदेशी कपास उपलब्ध होने पर वस्त्र उद्योग

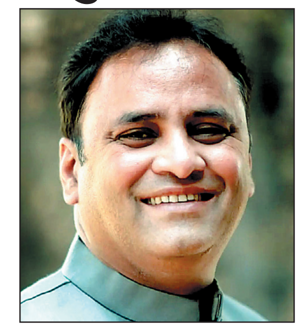

उसी को खरीदेगा. ऐसी स्थिति में देशी किसानों की उपज औने-पौने दामों पर बिकेगी या खरीदार ही नहीं मिलेंगे. यह किसानों को आर्थिक संकट की ओर धकेलने वाला निर्णय है, उन्होंने कहा.

मध्यप्रदेश, जो देश में कपास उत्पादन में सातवें स्थान पर है, पहले से ही गिरावट झेल रहा है.

> वर्ष 2019-20 में जहाँ 6.50 लाख हेक्टेयर में कपास बोया जाता था, वहीं 2024-25 में यह घटकर 5.37 लाख हेक्टेयर रह गया है. उत्पादन भी 18.01 लाख बेल्स से घटकर 15.35 लाख बेल्स होने का अनुमान है. यादव ने सरकार से आयात शुल्क बहाल करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी, घरेलू कपास की अनिवार्य खरीद और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर कदम न उठाने पर देशभर के लाखों कपास किसान गहरे संकट में फँस जाएंगे.

शराब दुकान पर एनएचआरसी का सशर्त समन

स्टाफ संवाददाता

भोपाल,03 सितम्बर. राजधानी की पॉश अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंड पर सोम ग्रुप द्वारा अवैध शराब दुकान-कम-बार संचालित किए जाने का मामला गंभीर रूप ले चुका है.

रहवासियों की लगातार शिकायतों के बावजूद आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अब यह मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 28 जुलाई 2025 को एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानुगो की पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया था.

> आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि भोपाल कलेक्टर शिकायत की जांच कर 15 दिन के भीतर कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीआर) प्रस्तुत करें. लेकिन 19 अगस्त को भेजी गई याद दिलाने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एनएचआरसी ने आबकारी आयुक्त और भोपाल जिला कलेक्टर को सशर्त समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली मुख्यालय में रिपोर्ट सहित उपस्थित होने का आदेश दिया है. त्रिपाठी ने प्रशासन और शराब माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि दुकान बंद कर लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन करेगी.

आज 40 इलाकों में बिजली कटौती

भोपाल, 3 सितंबर. राजधानी में बुधवार को करीब 40 इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी, जिससे इन इलाकों में बिजली बंद रहेगी. बुधवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर, अनंतपुर कोकता, लक्ष्मी टॉकीज रोड, नेहरू रोड, बेलदारपुरा, सेफिया कॉलेज रोड, अलीगंज, जुमेराती सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक हमीदिया रोड, इब्राहिमगंज, सज्जाद कॉलोनी, बाल विहार, दवा बाजार, नादरा बस स्टैंड, चेतन मार्केट, मलिक मार्केट, बरखेड़ी. सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शक्तिनगर ए, बी-सी सेक्टर, पंचवटी, दशहरा मैदान सेक्टर-2 सहित अन्य इलाकों में बिजली बंद रहेगी.

फर्जी फैकल्टी प्रकरण पर एफआईआर की मांग

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 03 सितम्बर. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राम मनोहर लोहिया नर्सिंग कॉलेज मे गंभीर अनियमितताओ और फर्जी दस्तावेज़ो के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने की साजिश का खुलासा किया है.

इस मामले मे एनएसयूआई ने मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अधिकारियो को शिकायत पत्र सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने और कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की मांग की है. एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि कॉलेज ने सत्र 2025-26 के लिए

ऑनलाइन आवेदन मे कंचन यादव को ट्यूटर बताया है, जबकि वे इस समय इंदौर से एमएससी नर्सिंग 2024-25 की पढ़ाई कर रही है. एक ही समय पर छात्रा का फैकल्टी के रूप मे नियुक्त होना सीधा फर्जीवाड़ा है. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि यह मामला नियमो का उल्लंघन है और भारतीय न्याय संहिता की धाराओ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

> रवि परमार ने आरोप लगाया कि 2025-26 सत्र मे लगभग 400 नर्सिंग कॉलेजो ने आवेदन किया है, जिनमे से 50 फीसदी मे गड़बड़िया पाई गई है. कई निजी कॉलेजो ने शासकीय नर्सिंग स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो को अपनी फैकल्टी के रूप मे दर्शाया है. एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि कठोर कार्रवाई नही हुई तो संगठन नर्सिंग काउंसिल का घेराव और राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे.

खाद्य विभाग ने किया निरीक्षण

भोपाल, 3 सितम्बर. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की टीम ने बैरागढ़ क्षेत्र में होटल और किराना दुकानों का निरीक्षण किया.

इस दौरान कारोबारियों को स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सामग्री को ढंककर रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही यह भी समझाइश दी गई कि किसी भी स्थिति में दूषित या खराब खाद्य सामग्री का विक्रय न करें. निरीक्षण के दौरान नैना चाट भंडार से आलू बड़े, बालाजी पूड़ी भंडार से मैदा, नीलम रेस्टोरेंट से सोयाबीन तेल और सौरभ प्वाइंट किराना से घी का नमूना लिया गया.

धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्त करने का मौका

भोपाल. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है. इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है. आवेदन 01 से 30 सितंबर तक लिए जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी के लिंक टैब में प्रदर्शित हैं. कंज्यूमर आईडी प्रविष्ट करते ही लंबित प्रकरण दिखाई देगा.

मूल्यांकन में पारदर्शिता के लिए बने कार्ययोजना

भोपाल,03 सितम्बर. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं के मूल्यांकन की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मूल्यांकन की कार्ययोजना बनाई जा रही है.

इससे उत्तर पुस्तिकाओं की सार्वजनिक उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी. वे भोपाल स्थित होटल पलाश रेसिडेंसी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे. मंत्री परमार ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं (कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, असमिया आदि) को सिखाने की योजना पर क्रियान्वयन

किया जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं. उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा, परंपरागत शोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें पूर्वजों की धरोहर पर गर्व का भाव जगाना होगा और 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान देना होगा.

> इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम की उपलब्धता, संकाय वृद्धि, कैम्पस प्लेसमेंट, सुरक्षा और संसाधनों को लेकर अपने सुझाव साझा किए. छात्रा रोशनी मालवीय ने ब्राम्ही लिपि में स्वलिखित रचना भेंट की. अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि विद्यार्थियों से संवाद का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा. कार्यक्रम में आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा, छात्र प्रतिनिधि अक्षत राजौरिया, दिशा शिवहरे सहित अधिकारी एवं प्राध्यापक उपस्थित थे.

रेलवे : तीन माह का सतर्कता जागरुकता सप्ताह अभियान

भोपाल, 03 सितम्बर. भारतीय रेल में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है.

वर्ष 2025 का यह अभियान 18 अगस्त से 17 नवम्बर तक चलेगा. इसी कड़ी में भोपाल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में 03 सितम्बर को मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम विषय पर विशेष सेमिनार का आयोजन डीआरएम कार्यालय सभागार में किया गया. इसमें सभी पर्यवेक्षकों को HRMS के नए मॉड्यूल में किए गए परिवर्तनों और विभिन्न टैब की विस्तृत जानकारी दी गई.

बीएचईएल से हाइड्रो जनरेटर शाफ्ट रवाना

भोपाल,03 सितम्बर. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में महाप्रबंधक एवं प्रमुख प्रदीप कुमार उपाध्याय ने पोलावरम हाइड्रो पावर प्लांट परियोजना की यूनिट-1 के लिए निर्मित बॉटम शाफ्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी विकास खरे, महाप्रबंधक (ईएम); रूपेश तेलंग, महाप्रबंधक (फीडर एवं ट्रांसफॉर्मर); जी.पी. बघेल, महाप्रबंधक (क्वालिटी); आलोक सेंगर, महाप्रबंधक (फैब्रिकेशन); जे. चटर्जी, महाप्रबंधक (हाइड्रो); नरेश सिंह, अतिरिक्त महाप्रबंधक (ईएम) सहित एचजीएम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.

लगभग 62 मीट्रिक टन वजनी यह बॉटम शाफ्ट अब तक निर्मित सबसे भारी हाइड्रो जनरेटर शाफ्ट है. इसका संपूर्ण मशीनिंग कार्य एचजीएम विभाग के ब्लॉक-2 मशीन शॉप में संपन्न हुआ.

चार माह के नवजात को जटिल हार्ट सर्जरी से मिली नई जिंदगी

▶ आरबीएसके कार्यक्रम से हुई साढ़े तीन लाख की फ्री सर्जरी

भोपाल, 03 सितंबर 2025. भोपाल के बाग मुगलिया क्षेत्र में रहने वाले राजन (परिवर्तित नाम) के घर में 4 महीने पहले बेटे के जन्म से खुशियां आईं. लेकिन जन्म के 15-20 दिन बाद ही बच्चा बार-बार बीमार रहने लगा.

तेज खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से परेशान माता-पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर स्थाई आराम नहीं मिला. इसी दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम बाग मुगलिया क्षेत्र की आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची. बच्चे के परीक्षण में हृदय रोग की आशंका होने पर माता-पिता को जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र लाकर विस्तृत जांच कराई गई. जयप्रकाश जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने जांच में पाया कि बच्चे को गंभीर हृदय रोग है और तत्काल सर्जरी जरूरी है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने निशुल्क इलाज की स्वीकृति दी और बच्चे को एसआरसीसी मुंबई रेफर किया गया.

आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 03 सितम्बर. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो पर अब भोपाल पुलिस सख्ती से पेश आएगी. पुलिस आयुक्त हरि नारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है.

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे. आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओ को भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करने के लिए नही करेगा. ऐसे किसी भी पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा. समूहो मे इस तरह की सामग्री रोकने की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी. कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, तथ्यो को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने, हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियो के लिए उकसाने वाले संदेश प्रसारित नही कर सकते. साथ ही, किसी संगठन या समुदाय को एकजुट होकर गैरकानूनी गतिविधियो मे शामिल होने के लिए उकसाने वाले संदेश भी प्रतिबंधित रहेंगे. आदेश मे साइबर कैफे संचालको के लिए भी सख्त नियम तय किए गए है. किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा. सभी आगंतुको का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान पत्र का विवरण रजिस्टर मे दर्ज करना अनिवार्य होगा साथ ही कैफे मे कैमरा लगाकर प्रत्येक आगंतुक की फोटो सुरक्षित रखना जरूरी होगा. इन आदेशो का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जायेगा. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन कदमो से शहर मे जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने मे मदद मिलेगी तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी.

समस्या ▶ स्टेशन के मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गड्ढों में भरा है पानी

रेलवे स्टेशन पर जलभराव से यात्रियों को भारी परेशानी

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 03 सितम्बर. भोपाल रेलवे स्टेशन इन दिनो यात्रियो के लिए मुसीबत का घर बना हुआ है मुख्य मार्ग से लेकर स्टेशन परिसर तक हर जगह बारिश का पानी भरा हुआ है.

लगातार हो रही बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए है पानी भरने से स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियो को न सिर्फ भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि कीचड़ और गंदगी ने स्थिति को और अधिक ख़राब कर दिया है. स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढो मे पानी भर गया, जिससे वाहन फिसलने और लोगो को आने जाने मे परेशानी हुई. वही, स्टेशन मे प्रवेश करने वाले पैदल यात्रियो को पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे है.

स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियो की संख्या रोजाना हजारो मे होती है, ऐसे मे जलभराव और गंदगी की समस्या से बीमारिया फैल सकती है साथ ही भोपाल की छवि भी धूमिल हो सकती है. यात्रियो ने यह भी शिकायत की है कि स्टेशन परिसर मे फिसलन के कारण कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके है. नगर निगम की लापरवाही के कारण यात्रियो को परेशानी हो रही है.

स्टेशन का मुख्य मार्ग और आस पास के इलाको मे हफ्तो से पानी भरा हुआ है. पानी निकासी के लिए अभी तक नगर निगम कोई एक्शन प्लान मे नजर नही आ रहा है. लगातार बारिश के कारण हाल और ख़राब हो रहा है. स्थानीय लोगो का कहना है कि यह समस्या हर साल बारिश के मौसम मे सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नही उठाया गया है. यात्रियो ने रेलवे प्रशासन और नगर निगम से अपील की है कि जल्द से जल्द जलभराव की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि यात्रियो को राहत मिल सके. फिलहाल, बारिश के चलते भोपाल जंक्शन पर गंदगी और पानी से जूझते यात्रियो को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

पूरे देश से रिकॉर्ड 746 प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश पुलिस की खास पहल

भोपाल, 3 सितम्बर 2025. मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित Cyber Innovation & Information Security Summit (CIIS) 2025 Hackathon को पूरे देश से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है.

यह कार्यक्रम युवाओं को साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दे रहा है. प्रतियोगिता में देश के 208 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 1159 टीमों ने पंजीकरण कराया. इनमें कुल 4459 छात्र-छात्राएँ शामिल हुए. सबसे अधिक टीमें मध्यप्रदेश से रहीं.

रिकॉर्ड प्रोजेक्ट सबमिशन

हैकाथॉन की अंतिम तिथि तक 746 प्रोजेक्ट जमा हुए, जो अब तक के किसी भी पुलिस हैकाथॉन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. यह युवाओं की बढ़ती रुचि और नवाचार क्षमता को दर्शाता है.

निष्पक्ष मूल्यांकन

प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन 28 विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, क्लियरट्रेल कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ और पुलिस साइबर सेल अधिकारी 2 से 4 सितम्बर तक करेंगे. इसके बाद 4 सितम्बर की शाम तक 30 सर्वश्रेष्ठ टीमों की सूची जारी होगी.